सं॰ 10(3)/2018-समन्वय

भारत सरकार

भारी उद्योग ऑर लोक उदयम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

.....

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक:29 जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मई, 2018 में महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार के बारे में |

मई, 2018 माह के दौरान भारी उद्योग विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित है|

दिनेश पाल सिंह

(दिनेश पाल सिंह)
अवर सचिव
दूरभाष: 23061045

सेवा मे,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागोंके सचिव।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नई दिल्ली ।
3. सयुंक्त सचिव (पी एवं ए) सूचना अवम प्रसारण मंत्रालय, कमरा नंबर 546, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
2. श्री एस जी पी वर्गीस, निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. आर्थिक सलाहकार, कमरा नंबर 225-ए, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. श्री पुण्णिन सेल्वन, पत्र सूचना कार्यालय, कमरा नंबर 263 'सी' उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

Department of Heavy Industry

Monthly Summary of Significant Activities for the month of May, 2018

This has reference to your DO letter No. 502/1/2/2014-CA-V dated August 5, 2014 regarding important issues/developments. The following significant activities have taken place during the month of May, 2018 in the Department of Heavy Industry (DHI).

1. Hon'ble Prime Minister laid the foundation stone for 3x800 MW Patratu Super Critical Thermal Power Station at Ramgarh District, Jharkhand on 25th May 2018, where BHEL is the EPC contractor for this project.
2. Hon'ble Prime Minister dedicated the 3x110 MW Kishanganga Hydro Electric Plant located in the state of Jammu and Kashmir to the nation. BHEL has supplied & commissioned electro-mechanical package of the project.
3. Hon'ble Minister (HI & PE) inaugurated the new facilities by the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRIP) at the International Centre for Automotive Technology (ICAT), Manesar in Haryana on 29th May 2018. These facilities include Noise, Vibration & Harshness (NVH) Lab, Passive Safety Lab (PSL), Electromagnetic Compatibility (EMC) Lab and Tyre Test Lab (TTL). NVH Lab is a unique facility in the entire country and ICAT is identified as the Centre of Excellence for testing in this area.
4. In an effort to encourage domestically manufactured automobile and automotive components, Department of Heavy Industry issued a notification on 18th May 2018 specifying a minimum local content of 65% and 60% for internal combustion engines based automobiles and automotive components respectively, for Public Procurement. This is a significant step in according purchase preference in public procurement to domestic products under Make in India.
5. For the FY 2017-18, Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) has achieved a Profit Before Tax (PBT) of Rs.1585 Crore compared to a PBT of Rs.628 Crore in the year 2016-17, registering a growth of 152%. Net profit (PAT) for the year stands at Rs. 807 Crore as against Rs. 496 Crore in the previous year. BHEL Board has approved to declare 91% total dividend for FY 2017-18 which will be the highest dividend in last four years.
6. In pursuance to direction of CGD in its meeting held on 28th February, 2018, DHI had carried out consultation with DRDO, DAE, D/o Space and Niti Aayog regarding NITI Aayog's recommendations on disinvestment of Heavy Engineering Corporation Limited (HEC), Ranchi. After deliberations considering the strategic nature of its engagement with HEC, DAE expressed their interest to take over administrative control of the company. CGD in its meeting held on 30th May, 2018 endorsed the recommendation of the DHI consultation and directed the Department of Atomic Energy to bring up a suitable proposal for the same.
7. The closing date for the three EoI's invited for disinvestment of CPSE's under the administrative control of DHI fell this month. While some responses have been received in

respect of Scooters India Ltd. (SIL), no responses were received for Bharat Pumps and Compressors Ltd. (BPCL) and Hindustan Newsprint Ltd. (HNL). Therefore, last dates of submission for these two CPSEs have been extended further.

8. Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry's took evidence of DHI on 'Professionalization of Board of CPSE's on 18-05-2018.
9. Sixth Meeting of Over Arching Committee of Advanced Ultra Super Critical (AUSC) Project, chaired by Principal Scientific Advisor to Govt. of India was held on 07.05.2018 to monitor the technical and financial status of the project.
10. Secretary, DHI co-chaired with Secretary (Power) a meeting of the High-Level Monitoring Committee on 15.05.2018 for implementation and monitoring of Maitree Super Thermal Power Project of 1320 (2X660 MW) at Rampal, Bagerhat in Bangladesh.
11. Two meetings were held in PMO under Chairmanship of Principal Secretary to PM to discuss the following Cabinet Notes circulated for Inter-Ministerial consultations:
    (i) Revival of Hindustan Paper Corporation (HPC) Ltd
    (ii) Closure of Nagaland Pulp and Paper Corporation Ltd
    (iii) Revival of NEPA Ltd
12. During the Month, BHEL got the order booking of around Rs. 2340 Crores including execution of 900 MW Hydropower Project in Nepal, which will be largest hydropower project in Nepal once completed.
13. A presentation on the EFC memo for FAME II scheme formulated by DHI after inter-ministerial consultations was made before CEO, NITI Aayog on 25th May 2018. Comments of NITI Aayog on the EFC memo area awaited.

****

भारी उद्योग विभाग

मई, 2018 के महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों का मासिक सार

महत्वपूर्ण मामलों/गतिविधियों से संबंधित दिनांक 5 अगस्त, 2014 के अर्द्धशासकीय पत्र सं. 502/1/2/2014-सीए-v का संदर्भ लें। भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) में मई, 2018 माह के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां सम्पन्न हुई हैं।

1. माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 25 मई, 2018 को जिला-रामगढ़, झारखंड में 3X800 मेगावाट पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला रखी जिसमें बीएचईएल इस परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदार है।
2. माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित 3X110 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। बीएचईएल ने परियोजना के इलेक्ट्रो-मेकेनिकल पैकेज की आपूर्ति एवं कमिशनिंग की।
3. माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने दिनांक 29 मई, 2018 को मानेसर, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) द्वारा नई सुविधाओं की शुरूआत की।इन सुविधाओं में शोर, कंपन एवं कठोरता (एनवीएच) प्रयोगशाला, पैस्सिव सेफ्टी लैब (पीएसएल), इलेक्ट्रोमैगनेटिक कम्पैटेबिलिटी (ईएमसी) प्रयोगशाला और टायर परीक्षण प्रयोगशाला (टीटीएल) शामिल हैं। एनवीएच प्रयोगशाला समूचे देश में एक विशिष्ट सुविधा है और इस क्षेत्र में परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में आईसीएटी की पहचान की है।
4. घरेलू रूप से विनिर्मित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कलपुर्जों को बढ़ावा देने के प्रयास में भारी उद्योग विभाग ने सार्वजनिक प्रापण हेतुआंतरिक दहन इंजन आधारित ऑटोमोबाइलो और ऑटोमोटिव कलपुर्जों के लिएक्रमशः न्यूनतम 65% और 60% स्थानीय मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 18 मई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादों के सार्वजनिक प्रापण हेतु खरीद में प्राथमिकता देने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने वर्ष 2016-17 में ₹628 करोड़ के पीबीटी की तुलना में ₹1585 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया, जिससे 152% की वृद्धि दर्ज हुई। पूर्व के वर्ष में ₹496 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹860 करोड़ का शुद्ध लाभ है। बीएचईएल बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल 91% के लाभांश की घोषणा का अनुमोदन दिया जो कि गत 4 वर्षों में सर्वाधिक लाभांश होगा।
6. दिनांक 28.02.2018 को आयोजित विनिवेश संबंधी कोर समूह (सीजीडी) ने हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के विनिवेश के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया। सीजीडी ने भारी उद्योग विभाग को रक्षा मंत्रालय (डीआरडीओ) और नीति आयोग से परामर्श करने की सलाह दी ताकि कंपनी की आस्तियों और प्रचालनों का इष्टतम लाभ लिया जा सके। भारी उद्योग विभाग ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा उत्पादन विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे संबंधित स्टेकहोल्डरों को भी शामिल करके विस्तार करने का निर्णय लिया।अप्रैह माह में सभी स्टेकहोल्डरों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। अंत में, काफी विचार-विमर्श के बाद एचईसी के साथ अपने रणनीतिक प्रकृति के समावेशन पर विचार करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग ने कंपनी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। दिनांक 30 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में सीजीडी ने भारी उद्योग विभाग की सिफारिशों पर विचार

किया। सीजीडी ने भारी उद्योग विभाग की सिफारिशों का समर्थन किया और परमाणु ऊर्जा विभाग को इसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव लाने का निदेश दिया।

7. उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 18.05.2018 को "सीपीएसई के बोर्ड का व्यवसायीकरण" पर भारी उद्योग विभाग का साक्ष्य लिया।
8. परियोजना की तकनीकी और आर्थिक स्थिति की निगरानी करने के लिए दिनांक 07.05.2018 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार की अध्यक्षता में उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) की ओवर आर्चिंग समित की 6वीं बैठक आयोजित की।
9. बांग्लादेश के रामपाल, बेगरहट में 1320 (2X660 मेगावाट) की मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु सचिव, भारी उद्योग विभाग ने सचिव (विद्युत) के साथदिनांक 15.05.2018 को एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति की एक बैठक की सह-अध्यक्षता की।
10. अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित की गई निम्नलिखित मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पीएमओ में दो बैठकें आयोजित की गईं:
    1. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) लिमिटेड का पुनरुद्धार।
    2. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को बंद किया जाना।
    3. नेपा लिमिटेड का पुनरुद्धार
11. माह के दौरान, बीएचईएल को नेपाल में 900 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजना के निष्पादन सहित लगभग ₹2340 करोड़ के आदेश प्राप्त हुए जोकि पूर्ण होने के बाद नेपाल में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना होगी।
12. अंतरमंत्रालयी परामर्श के बाद भारी उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई फेम-II योजना के लिए ईएफसी मेमो पर दिनांक 25 मई, 2018 को सीईओ, नीति आयोग के सामनेएक प्रस्तुतीकरण किया गया। ईएफसी मेमो पर नीति आयोग की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

****